

दूसरा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), भारतीय रिज़र्व बैंक का संकल्प*

मौद्रिक नीति समिति ने आज की अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि –

- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 6.00 प्रतिशत से 25 आधार अंक कम करके 5.75 प्रतिशत किया जाए।

परिणामस्वरूप, एलएएफ के तहत प्रतिवर्ती रेपो दर 5.50 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर तथा बैंक दर 6.00 प्रतिशत पर समायोजित हो जाएगी।

एमपीसी ने मौद्रिक नीति रुख को तटस्थ से उदार रुख में बदलने का भी निर्णय लिया है।

ये निर्णय वृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति के 4 प्रतिशत के मध्यावधिक लक्ष्य को +2/-2 प्रतिशत के दायरे में हासिल करने के उद्देश्य से भी है।

इस निर्णय के समर्थन में प्रमुख विवेचनों का वर्णन नीचे दिए गए विवरण में किया गया है।

आकलन

वैश्विक अर्थव्यवस्था

2. वैश्विक आर्थिक गतिविधि ने 2019 की पहली तिमाही में कुछ हद तक बेहतर प्रदर्शन के बाद गति खो दी है, जो आगे व्यापार और विनिर्माण गतिविधि में मंदी में प्रतिबिम्बित हुई है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) के बीच, अमेरिका में आर्थिक गतिविधि पहली तिमाही में मजबूत हुई, जो उच्च सरकारी खर्च,

निजी निवेश में वृद्धि और कम व्यापार घाटे द्वारा समर्थित है। तथापि, फ़ैक्टरी गतिविधि और खुदरा बिक्री अप्रैल में मंद हुई। मंद औद्योगिक गतिविधि और कमजोर व्यावसायिक आत्मविश्वास के कारण यूरो क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि कमजोर बनी हुई है। दूसरी तिमाही में यूरो क्षेत्र में अग्रणी संकेतक अतिरिक्त मंदी की ओर इशारा कर रहे हैं। यूके में, पहली तिमाही में उच्च खुदरा बिक्री और सरकारी व्यय से जीडीपी की वृद्धि हुई। तथापि, ब्रेक्सिट से संबंधित अनिश्चितता के कारण संभावनाएं अस्पष्ट हैं। शुद्ध निर्यात लाभ और सार्वजनिक निवेश में वृद्धि पर जापानी अर्थव्यवस्था पहली तिमाही में तेज हुई। अप्रैल में, औद्योगिक उत्पादन में सुधार हुआ, जबकि खुदरा बिक्री गिर गई।

3. कई उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में आर्थिक गतिविधि धीमी हो गई है। 2019 की पहली तिमाही में, चीनी अर्थव्यवस्था पिछली तिमाही की तरह तेज गति से बढ़ी, जो आम उम्मीदों की अपेक्षा थोड़ी अधिक थी। तथापि, औद्योगिक उत्पादन और खुदरा बिक्री पर आने वाले आकड़ों से पता चलता है कि विकास की गति दूसरी तिमाही में कमजोर हो सकती है। रूसी अर्थव्यवस्था, जिसने 2018 की चौथी तिमाही में वसूली के कुछ संकेत दिखाए थे, जो मंद घरेलू गतिविधि और व्यापार के कारण पहली तिमाही में कमजोर हो गई। पहली तिमाही में दक्षिण अफ्रीका में आर्थिक गतिविधियों में मुख्य रूप से विनिर्माण गतिविधि में तेज गिरावट आई है। ब्राजील की अर्थव्यवस्था 2016 के बाद पहली बार पहली तिमाही में संकुचित हुई और यह आशंका है कि यह मंदी में लौट सकती है।

4. कच्चे तेल की कीमतें अस्थिर बनी हुई हैं, जो ओपेक प्लस के उत्पादन रुख से बढ़ती मांग-आपूर्ति की स्थिति को दर्शाती है, जो बढ़ती शेल उत्पादन, वैश्विक मांग और भू-राजनीतिक चिंताओं को कमजोर कर रही है। अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने से सोने की कीमतें कमजोर हुईं; तथापि, व्यापार तनाव बढ़ने पर मई के आखिरी सप्ताह से कीमतों में तेजी आई, जिसने आश्रय संपत्ति के रूप में अपनी मांग को फिर से बढ़ाया। मुद्रास्फीति कई अर्थव्यवस्थाओं में लक्ष्य से नीचे बनी हुई है, यद्यपि इसने मार्च के बाद से तेजी दिखाई है।

5. वित्तीय बाजार यूएस-चीन व्यापार वार्ता और ब्रेक्सिट के आसपास की अनिश्चितताओं से प्रेरित होकर परिचालित हो

* 06 जून, 2019 को जारी किया गया।

रहे हैं। अमेरिका में, इक्विटी बाजार ने मई के शुरुआत में चीन और हाल ही में, मेक्सिको के साथ व्यापार तनाव के बढ़ने के बाद से कुछ बिक्री दबावों को अनुभव किया गया है। बढ़ती भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं पर जोखिम बढ़ने के कारण और वैश्विक बाजार की संभावनाओं को कमजोर करने के कारण अधिकांश ईएमई में इक्विटी बाजारों में मंदी आई। यूएस में अप्रैल में पहली तिमाही में बेहतर जीडीपी डेटा के कारण बॉन्ड प्रतिफल में वृद्धि हुई, लेकिन आर्थिक आंकड़ों और एक डॉविश मौद्रिक नीति के रुख की उम्मीद के कारण इसमें मई में गिरावट आई। जर्मनी में बॉन्ड प्रतिफल में कमजोर आर्थिक आंकड़ों के कारण नकारात्मकता देखी गयी; जापान में, वे निरंतर उदरात्मकता के संकेत पर नकारात्मक बने रहे। कई ईएमई में, बॉण्ड प्रतिफल आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मौद्रिक नीति को अपनाने के साथ केंद्रीय बैंकों के साथ गिर रहे हैं। मुद्रा बाजारों में, पहली तिमाही के लिए अपेक्षित घरेलू आर्थिक आंकड़ों की तुलना में अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ। अधिकांश ईएमई मुद्राओं में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरावट आई है।

घरेलू अर्थव्यवस्था

6. घरेलू अर्थव्यवस्था की ओर रुख करते हुए, 31 मई, 2019 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने 2018-19 की चौथी तिमाही के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के तिमाही अनुमान और 2018-19 के लिए राष्ट्रीय आय का अंतिम अनुमान जारी किया। 2018-19 के लिए जीडीपी की वृद्धि दर वर्ष-दर-वर्ष (वाई-ओ-वाई) 6.8 प्रतिशत आंकी गई है, जो कि निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) में नीचे की ओर संशोधित और निर्यात मंदी के कारण 28 फरवरी को जारी दूसरे अग्रिम अनुमान से 20 आधार अंक नीचे है। तिमाही के आंकड़ों से पता चलता है कि घरेलू आर्थिक गतिविधि तीसरी तिमाही में 6.6 प्रतिशत और 2017-18 की चौथी तिमाही में 8.1 प्रतिशत से 2018-19 की चौथी तिमाही में तेजी से घटकर 5.8 प्रतिशत हो गई। पिछली पांच तिमाहियों में दोहरे अंकों में रहने के बाद सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) की वृद्धि तेजी से घटकर 3.6 प्रतिशत रह गई। निजी खपत की वृद्धि भी कम हुई। आयात के सापेक्ष निर्यात में तेज गिरावट के कारण शुद्ध निर्यात से कुल मांग पर चौथी तिमाही में वृद्धि हुई। तथापि, सरकारी अंतिम उपभोग

व्यय (जीएफसीई) में बड़ी वृद्धि के कारण विकास में समग्र मंदी आई थी।

7. आपूर्ति पक्ष पर, 2018-19 की चौथी तिमाही में रबी उत्पादन में गिरावट के कारण यद्यपि मामूली रूप से, कृषि और संबद्ध गतिविधियां संकुचित रहीं। तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, 2018-19 में 283.4 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन मुख्य रूप से रबी चावल, दालों और मोटे अनाजों के कम उत्पादन के कारण पिछले वर्ष की तुलना में 0.6 प्रतिशत कम था। तथापि, पहले के अनुमानों के सापेक्ष खाद्यान्न उत्पादन में तेजी रही है। 16 मई 2019 तक 72.6 मिलियन टन खाद्यान्न का स्टॉक निर्धारित बफर मानदंडों से 3.4 गुना अधिक था। विनिर्माण गतिविधियों में वृद्धि पिछली तिमाही के 6.4 प्रतिशत से तेजी से घट कर 3.1 प्रतिशत हुई। तथापि, सेवा क्षेत्र की वृद्धि, वित्तीय, भू संपदा और पेशेवर सेवाओं एवं सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं द्वारा समर्थन के कारण तेज रही। इसके विपरीत, विनिर्माण गतिविधि स्पष्ट रूप से धीमी हो गई।

8. चौथी तिमाही से आगे बढ़ते हुए, भारत के मौसम विभाग (आईएमडी) ने भविष्यवाणी की है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून की बारिश (जून से सितंबर) लंबी अवधि के औसत (एलपीए) के 96 प्रतिशत तक सामान्य रहने की संभावना है। प्रशांत क्षेत्र की मौजूदा कमजोर एल नीनो परिस्थिति मानसून के दौरान जारी रहने की संभावना है। तथापि, वर्तमान में प्रचलित तटस्थ हिंद महासागर डिपोल (आईओडी) की स्थिति मानसून के मौसम के बीच में सकारात्मक हो सकती है और इसके बाद बनी रह सकती है, जो बारिश के दृष्टिकोण से शुभ संकेत है।

9. अप्रैल में, मुख्य रूप से कोयला, कच्चे तेल, उर्वरक और सीमेंट में गिरावट के कारण आठ प्रमुख उद्योगों में तेजी से गिरावट हुई। बैंकों से बड़े उद्योगों में ऋण प्रवाह मजबूत हुआ, यद्यपि वे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए कम रहे। रिज़र्व बैंक की आदेश पुस्तिका के प्रारंभिक परिणामों के आधार पर, इन्वेंट्री और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण (ओबीआईसीयूएस), विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता उपयोग (सीयू) तीसरी तिमाही में 75.9 प्रतिशत की तुलना में चौथी तिमाही में बढ़कर 77 प्रतिशत हो गया; तथापि, मौसम के हिसाब से समायोजित क्षमता उपयोग (सीयू) तीसरी तिमाही में 75.8 प्रतिशत की तुलना में मामूली रूप में फिसल

कर चौथी तिमाही में 75.2 प्रतिशत रहा। 2019-20 की पहली तिमाही में औद्योगिक आउटलुक सर्वेक्षण (आईओएस) का व्यवसाय मूल्यांकन सूचकांक (बीएआई) पिछली तिमाही में अपने स्तर पर अपरिवर्तित रहा। पूंजीगत वस्तुओं का आयात- निवेश गतिविधि का एक प्रमुख संकेतक- अप्रैल में मंद बना रहा। तथापि, विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) मई में उत्पादन, नए आदेश और रोजगार में मजबूती के कारण 52.7 तक पहुंच गया।

10. उच्च आवृत्ति संकेतक सेवा क्षेत्र में गतिविधि में मंदी की ओर इशारा करते हैं। अप्रैल में वाणिज्यिक वाहनों, ट्रैक्टरों, सवारी कारों और तीन और दो पहिया वाहनों की बिक्री संकुचित रही। रेलवे माल ढुलाई विकास में गिरावट आई है। मार्च में घरेलू हवाई यात्री यातायात वृद्धि में कमी हुई, लेकिन अप्रैल में मामूली रूप से परिवर्तित हुई। निर्माण गतिविधि के दो प्रमुख संकेतक अर्थात् सीमेंट उत्पादन और इस्पात की खपत अप्रैल में धीमी हो गयी। पीएमआई सेवा सूचकांक मई में नए व्यवसायों के विकास में धीमी वृद्धि के कारण 50.2 तक पहुंच गया।

11. सीपीआई में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन द्वारा मापी गई खुदरा मुद्रास्फीति मार्च में इसके 2.9 प्रतिशत के स्तर से अप्रैल में अपरिवर्तित रही, खाद्य और ईंधन को छोड़कर कम मुद्रास्फीति ने खाद्य और ईंधन समूहों में उच्च मुद्रास्फीति को समायोजित कर दिया।

12. अप्रैल में खाद्य मुद्रास्फीति के प्रिंट में मार्च में 0.7 प्रतिशत की तुलना में 1.4 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। खाद्य समूह के भीतर, सब्जियां नौ महीने के अपस्फीति से बाहर आईं। तथापि, तीन उप-समूह, अर्थात्, फल, दाल और चीनी अप्रैल में अपस्फीति में बने रहे, यद्यपि अपस्फीति की मात्रा कम हुई। अन्य खाद्य उप-समूहों के बीच, दूध, तेल और वसा, मसाले, गैर-अल्कोहलीक पेय पदार्थों और तैयार भोजन की कीमतों में सुधार हुआ, जबकि मांस, मछली और अंडों की कीमतों में मुद्रास्फीति बढ़ गई।

13. ईंधन और प्रकाश समूह की मुद्रास्फीति तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी के कारण फरवरी के 1.2 की तुलना में अप्रैल में बढ़कर 2.6 प्रतिशत हो गई। सब्सिडाइज्ड केरोसिन तेल में मुद्रास्फीति भी बढ़ी है, जो इसके प्रशासित मूल्य में कैलिब्रेटेड वृद्धि के प्रभाव को दर्शाती है।

तीन महीनों के बाद बिजली की कीमतें अप्रैल में अपस्फीति के बाहर चली आईं। ग्रामीण ईंधन की खपत की वस्तुओं की कीमतें - जलाऊ लकड़ी, चिप्स और गोबर केक - अपस्फीति में चले गए।

14. सीपीआई मुद्रास्फीति खाद्य और ईंधन को छोड़कर मार्च में 5.1 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल में 4.5 प्रतिशत तक तेजी से गिर गई - अप्रैल 2017 के बाद से यह सबसे बड़ी मासिक गिरावट है। घरेलू सामान और सेवाओं के साथ मुद्रास्फीति में मंदी व्यापक रूप से आधारित था और व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव उप-समूह ने अप्रैल में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की; जून 2017 के बाद से आवास मुद्रास्फीति सबसे कम थी जो शहरी क्षेत्रों में मकान किराए में नरमी को दर्शाती हैं। नई अखिल भारतीय सीपीआई श्रृंखला में कपड़ों और जूतों की महंगाई ने अपने ऐतिहासिक स्तर को भी छुआ। शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन और संचार में मुद्रास्फीति मंद रही।

15. रिजर्व बैंक के सर्वेक्षण के मई 2019 में घरेलू मुद्रास्फीति के अनुमान में पिछले दौर की तुलना में तीन महीने के आगे होरीज़ोन के लिए 20 आधार अंक की गिरावट आई, लेकिन एक साल के आगे होरोज़ोन के लिए यह अपरिवर्तित रहा। तथापि, रिजर्व बैंक के औद्योगिक दृष्टिकोण सर्वेक्षण में भाग लेने वाली विनिर्माण फर्मों को उम्मीद है कि उच्चतर कच्चे माल की लागत और दूसरी तिमाही में वेतन के कारण इनपुट लागत दबाव तेज होगा। कृषि और औद्योगिक कच्चे माल दोनों में इनपुट मूल्य दबाव कम हुआ। ग्रामीण मजदूरी और संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की लागत में नाममात्र वृद्धि स्थिर रही।

16. अप्रैल और मई के अधिकांश समय के दौरान घाटे में रहने पर सरकारी खर्च पर रोक लगाने के कारण जून की शुरुआत में सिस्टम में चलनिधि ₹ 66,000 करोड़ (₹ 660 बिलियन) के औसत दैनिक अधिशेष में बदल गई। रिजर्व बैंक ने एलएएफ के तहत दैनिक शुद्ध औसत आधार पर अप्रैल में ₹ 70,000 करोड़ (₹ 700 बिलियन) और मई में ₹ 33,400 करोड़ (₹ 334 बिलियन) चलनिधि उपलब्ध करवाया। सिस्टम में स्थायी चलनिधि उपलब्ध करने हेतु मई में दो ओएमओ की नीलामी का आयोजन किया, जिसकी राशि ₹ 25,000 करोड़ (₹ 250 बिलियन) थी और अप्रैल में 3 वर्ष की अवधि हेतु 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹ 34,874 करोड़) की खरीद/ बिक्री स्वैप नीलामी आयोजित

की गई। भारत औसत मांग मुद्रा दर (डबल्यूएसीआर) - मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य - मोटे तौर पर पॉलिसी रेपो दर के साथ संरेखित रहा: इसने अप्रैल में 6 बीपीएस तक पॉलिसी रेपो दर (औसतन) से ऊपर, लेकिन मई में पॉलिसी रेपो दर से नीचे 6 बीपीएस तक कारोबार किया। रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि वह 13 जून, 2019 को ₹ 15,000 करोड़ (₹ 150 बिलियन) की ओएमओ खरीद नीलामी आयोजित करेगा।

17. फरवरी और अप्रैल 2019 में पॉलिसी रेपो दर में 50 बीपीएस की संचयी कमी का ट्रांसमिशन नए रुपये ऋणों पर भारत औसत उधार दर (डबल्यूएएलआर) पर 21 बीपीएस था। तथापि, बकाया रूपए ऋण पर डबल्यूएएलआर में 4 बीपीएस की वृद्धि हुई क्योंकि पिछले ऋणों पर उच्च दर जारी रहे। दीर्घावधि मुद्रा बाजार लिखत पर ब्याज दर व्यापक रूप से ओवरनाइट डबल्यूएसीआर के साथ संबद्ध रहे, जो नीतिगत दर में कमी के पूर्ण ट्रांसमिशन को परिलक्षित करते हैं।

18. मार्च 2019 की निर्यात में पायी गयी 11.8 प्रतिशत की वृद्धि बरकरार नहीं रह सकी: अप्रैल 2019 में इंजीनियरिंग वस्तुओं, रत्नों और आभूषणों और चमड़े के उत्पादों में गिरावट के कारण उनमें 0.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अप्रैल 2019 में पिछले महीने के मुकाबले पेट्रोलियम (कच्चे तेल और उत्पाद), सोना और मशीनरी के आयात में उछाल के कारण आयात कुछ तेज गति से बढ़ा। इससे व्यापार घाटे में क्रमिक रूप से और वर्ष-दर-वर्ष आधार पर वृद्धि हुई। अनंतिम आंकड़ों से पता चलता है कि 2018-19 की चौथी तिमाही में निवल सेवा निर्यात एक साल पहले के उनके स्तर की तुलना में काफी अधिक था, जो चालू खाता शेष के लिए अच्छा है। वित्तीय पक्ष पर, निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह 2018-19 की चौथी तिमाही में एक साल पहले की तुलना में अधिक मजबूत रहे। मार्च 2019 में तेज रिकवरी के बाद, 2019-20 में अप्रैल-मई में निवल विदेशी पोर्टफोलियो अंतर प्रवाह अमरीकी डॉलर 2.3 बिलियन पर अपेक्षाकृत मामूली था। जबकि इस अवधि के दौरान इक्विटी खंड को निवल अंतर प्रवाह प्राप्त हुआ, ऋण खंड में निवल बहिर्वाह देखा गया। 31 मई 2019 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 421.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

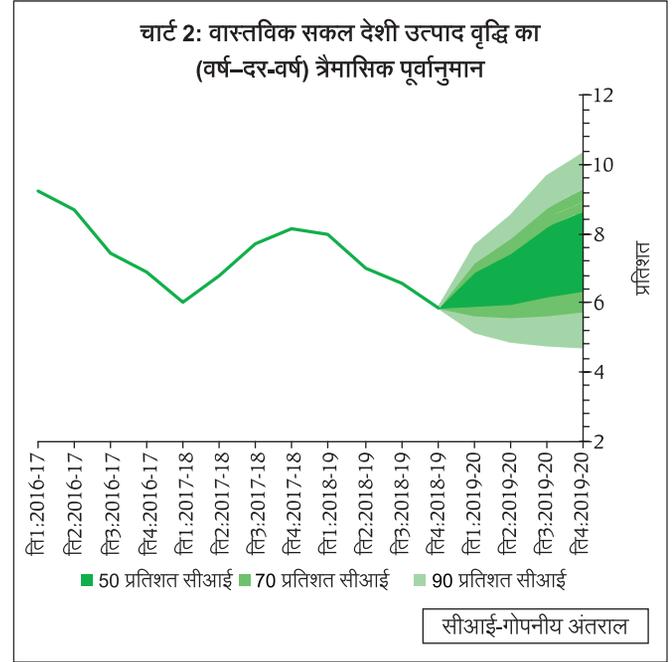
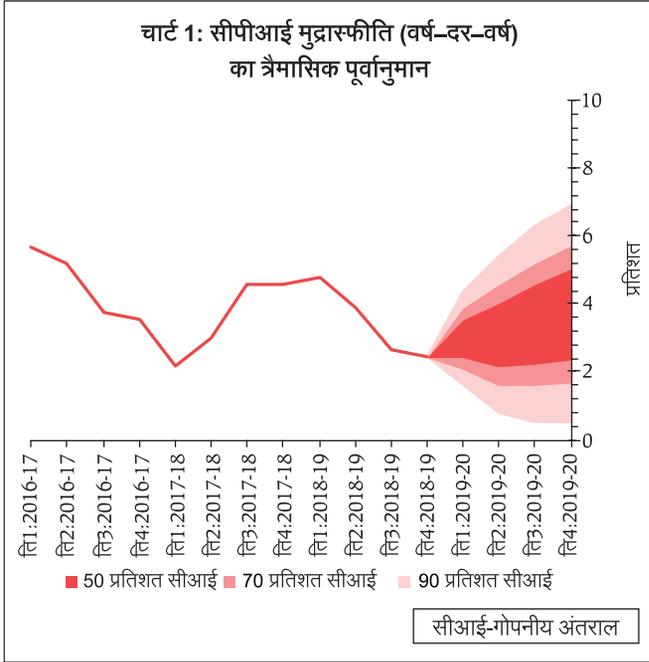
संभावनाएं

19. अप्रैल 2019 की द्विमासिक मौद्रिक नीति संकल्प में, मोटे तौर पर संतुलित जोखिम के साथ सीपीआई मुद्रास्फीति को 2018-19 की चौथी तिमाही के लिए 2.4 प्रतिशत, 2019-20 की पहली छमाही के लिए 2.9-3.0 प्रतिशत और 2019-20 की दूसरी छमाही के लिए 3.5-3.8 प्रतिशत का अनुमान लगाया गया था। चौथी तिमाही में 2.5 प्रतिशत हेडलाइन मुद्रास्फीति के परिणाम अप्रैल नीति अनुमानों के अनुरूप थे।

20. 2019-20 के लिए आधारभूत मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र कई कारकों द्वारा निर्धारित है। सबसे पहले, सब्जियों की कीमतों में गर्मी में उछाल उम्मीद से ज्यादा तेज रहा है, हालांकि इसमें शरद ऋतु और सर्दियों के दौरान एक बड़ा उलटफेर भी आ सकता है। अधिक हाल की जानकारी भी कई खाद्य पदार्थों की कीमतों में व्यापक पिक-अप का संकेत देती है। इसने खाद्य मुद्रास्फीति के निकटवर्ती प्रक्षेपवक्र को एक ऊपर की ओर का पूर्वाग्रह प्रदान किया है। दूसरा, अप्रैल में खाद्य और ईंधन को छोड़कर मुद्रास्फीति में घरेलू और बाहरी मांग की स्थिति के कमजोर होने से मुद्रास्फीति में 60 बीपीएस की तीव्र गिरावट आई है; इसने शेष वर्ष के लिए मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र को एक निम्न ओर का पूर्वाग्रह प्रदान किया है। तीसरा, कच्चे तेल की कीमतें अस्थिर बनी हुई हैं। हालांकि, सीपीआई मुद्रास्फीति पर इसका प्रभाव अब तक अपूर्ण है। चौथा, परिवारों की निकट अवधि की मुद्रास्फीति की उम्मीदें मध्यम रही हैं। इन कारकों को और हाल की नीतिगत दर में कटौती को ध्यान में रखते हुए और 2019 में एक सामान्य मानसून की अपेक्षाओं के साथ, मोटे तौर पर संतुलित जोखिमों के साथ सीपीआई मुद्रास्फीति को 2019-20 की पहली छमाही के लिए 3.0-3.1 प्रतिशत और 2019-20 की दूसरी छमाही के लिए 3.4-3.7 प्रतिशत तक संशोधित किया गया है। (चार्ट 1)।

21. मानसून से संबंधित अनिश्चितताओं, सब्जियों की कीमतों में बेमौसमी उतार-चढ़ाव, अंतरराष्ट्रीय ईंधन की कीमतों और उससे प्रभावित घरेलू कीमतों, भू-राजनीतिक तनावों, वित्तीय बाजार की अस्थिरता और राजकोषीय परिदृश्य से आधारभूत मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र के आसपास जोखिम उत्पन्न होते हैं।

22. अप्रैल की नीति में, 2019-20 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर समान रूप से संतुलित जोखिमों के साथ 7.2



प्रतिशत - पहली छमाही के लिए 6.8-7.1 प्रतिशत की सीमा में और दूसरी छमाही के लिए 7.3-7.4 प्रतिशत की सीमा में अनुमानित की गई थी। 2018-19 की चौथी तिमाही के आंकड़े बताते हैं कि घरेलू निवेश गतिविधि कमजोर हुई है और निर्यात में कमी से कुल मांग आंशिक रूप से कम हुई है। व्यापार युद्धों में वृद्धि के कारण कमजोर वैश्विक मांग भारत के निर्यात और निवेश गतिविधि को और प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा, निजी खपत, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, हाल के महीनों में कमजोर हुई है। हालांकि, सकारात्मक पक्ष पर, राजनीतिक स्थिरता, उच्च क्षमता उपयोग, दूसरी तिमाही में व्यापार की उम्मीदों में उछाल, शेयर बाजार की बेहतर स्थिति और व्यावसायिक क्षेत्र के लिए उच्च वित्तीय प्रवाह निवेश गतिविधि में वृद्धि कर सकते हैं। उपरोक्त कारकों और हाल की नीति दर में कटौती के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, 2019-20 के लिए जीडीपी की वृद्धि अप्रैल की नीति के 7.2 प्रतिशत से नीचे की ओर संशोधित होकर -2019-20 की पहली छमाही के लिए के लिए 6.4-6.7 प्रतिशत और दूसरी छमाही के लिए 7.2-7.5 प्रतिशत - की सीमा में समान रूप से संतुलित जोखिमों के साथ 7.0 प्रतिशत हो गई है (चार्ट 2)।

23. एमपीसी नोट करता है कि अप्रैल 2019 की नीति की तुलना में उत्पादन अंतराल के और अधिक विस्तृत हो जाने के

कारण विकास आवेगों में काफी कमी आई है। निजी उपभोग वृद्धि में निरंतर वृद्धि के साथ-साथ निवेश गतिविधियों में तीव्र मंदी चिंता का विषय है। पिछली दो नीतियों में नीतिगत दरों में कटौती के अपेक्षित प्रसारण को ध्यान में रखते हुए भी हेडलाइन मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र एमपीसी को दिए गए लक्ष्य के नीचे रहा है। इसलिए, कुल मांग को बढ़ाने के लिए और विशेष रूप से निजी निवेश गतिविधि को फिर से मजबूत करने के लिए एमपीसी के पास अपने लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के अनुरूप विकास चिंताओं को समायोजित करने की गुंजाइश है।

24. इस पृष्ठभूमि में, एमपीसी के सभी सदस्यों (डॉ. चेतन घाटे, डॉ. पामी दुआ, डॉ. रविंद्र एच. ढोलकिया, डॉ. माइकल देवव्रत पात्रा, डॉ. विरल वी. आचार्य और श्री शक्तिकांत दास) ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 25 आधार अंकों से कम करने और मौद्रिक नीति रुख को तटस्थ से उदार रुख में बदलने का भी निर्णय लिया है।

25. एमपीसी की बैठक के कार्यवृत्त 20 जून 2019 तक प्रकाशित किए जाएंगे।

26. एमपीसी की अगली बैठक 5 से 7 अगस्त 2019 के दौरान आयोजित की जाएगी।

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

यह वक्तव्य विनियमन और पर्यवेक्षण को मजबूत करने; वित्तीय बाजारों को व्यापक और मजबूत बनाने; भुगतान और निपटान प्रणाली में सुधार करने के लिए विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीति उपायों को निर्धारित करता है।

I. विनियमन और पर्यवेक्षण

1. बैंकों के लिए लिवरेज अनुपात

अत्यधिक लिवरेज के जोखिमों को कम करने के लिए, बैंकिंग पर्यवेक्षण (बीसीबीएस) पर बासल समिति ने बेसल III लिवरेज अनुपात (एलआर) को मौजूदा जोखिम-आधारित पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक सरल, पारदर्शी और गैर-जोखिम आधारित उपाय के रूप में बनाया। रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए एलआर पर ढांचे के संदर्भ में, 4.5% के सांकेतिक एलआर पर बैंकों की निगरानी की गई। इन दिशानिर्देशों ने प्रकटीकरण का उद्देश्य से और बैंकों द्वारा समानांतर चलने के आधार के रूप में भी कार्य किया है। अंतिम न्यूनतम एलआर आवश्यकता को 2017 के अंत तक बासल समिति द्वारा निर्धारित अंतिम नियमों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना था।

बीसीबीएस ने हाल ही में यह निर्णय दिया है कि बैंकों को हर समय न्यूनतम 3% एलआर आवश्यकता को पूरा करना चाहिए (बासल III: संकट के बाद के सुधारों को अंतिम रूप देना, दिसंबर 2017)। दोनों पूंजीगत माप और एक्सपोजर माप की गणना तिमाही-अंत के आधार पर की जानी है। तथापि, बैंक, पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन, जब तक कि वे ऐसा लगातार रूप से करते रहेंगे अधिक बारंबारता (जैसे, दैनिक या मासिक औसत) के साथ गणना कर सकते हैं।

वित्तीय स्थिरता को ध्यान में रखते हुए और बासल III मानकों के साथ सामंजस्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (डीएसआईबी) के लिए न्यूनतम एलआर 4% और अन्य बैंकों के लिए 3.5% होना चाहिए। इस संबंध में अनुदेश जून 2019 की समाप्ति से पहले जारी किए जाएंगे।

2. लघु वित्त बैंकों को मांग पर लाइसेंस

27 नवंबर 2014 को निजी क्षेत्र में "भुगतान बैंकों" और "लघु वित्त बैंकों" को लाइसेंस के लिए दिशानिर्देशों में यह अधिसूचित

किया गया था कि इन बैंकों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, रिज़र्व बैंक 'मांग पर' लाइसेंस देने का विचार करेगा।

लघु वित्त बैंकों के मामले में, ऐसे दस बैंकों को लाइसेंस जारी किया गया था। इसके अलावा, दस लघु वित्त बैंकों में से आठ को रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में भी शामिल किया गया है। लघु वित्त बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा से पता चलता है कि उन्होंने अपने प्राथमिकता क्षेत्र के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है और इस प्रकार वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए अपने जनादेश को प्राप्त किया है। इसलिए, छोटे उधारकर्ताओं की बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए अधिक खिलाड़ियों को शामिल किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए, अगस्त 2019 के अंत तक लघु वित्त बैंकों को 'मांग पर' लाइसेंस के लिए ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी करने का प्रस्ताव है।

यह भी निर्णय किया गया है कि बैंकों की इस श्रेणी को 'मांग पर' लाइसेंस देने के लिए विचार करने से पहले भुगतान बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता है।

3. मूल निवेश कंपनियों (सीआईसी) के लिए विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचा

अगस्त 2010 में, रिज़र्व बैंक ने अन्य महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के सापेक्ष एक होल्डिंग कंपनी के कारोबार मॉडल में अंतर को पहचानते हुए प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण मूल निवेश कंपनियों (सीआईसी) के विनियमन के लिए एक अलग रूपरेखा पेश की। इन वर्षों में, कॉर्पोरेट समूह संरचनाएँ कई लेयरिंग और लीवरेजिंग से अधिक जटिल हो गई हैं, जिसके कारण सार्वजनिक धन तक उनकी पहुँच के कारण वे वित्तीय प्रणाली से अधिक अंतर-संबद्ध हो गए हैं। आगे, हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए, सीआईसी के कॉर्पोरेट शासन ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता है। इसके अनुसार, सीआईसी पर लागू विनियामक दिशानिर्देशों और पर्यवेक्षी ढांचे की समीक्षा के लिए एक कार्य समूह का गठन करने का निर्णय लिया गया है।

II. वित्तीय बाजार

4. चलनिधि प्रबंधन ढांचे की समीक्षा करने के लिए आंतरिक कार्य समूह

रिजर्व बैंक के चलनिधि प्रबंधन ढांचे की अंतिम बार 2014 में समीक्षा की गई थी। कुल मिलाकर वर्तमान में संपूर्ण चलनिधि प्रबंधन ढांचे ने अच्छा काम किया है, यह कुछ हद तक जटिल भी हो गया है। विभिन्न बाजार सहभागियों द्वारा चलनिधि की स्थिति का आकलन अलग-अलग तरीके से किया गया है और यह हमेशा अर्थव्यवस्था में वास्तविक प्रणालीगत चलनिधि की स्थिति के अनुरूप नहीं है।

तदनुसार, रिजर्व बैंक द्वारा मौजूदा चलनिधि प्रबंधन ढांचे की व्यापक समीक्षा करने और उपायों का सुझाव देने, जिसमें दूसरी बातों के अलावा, (i) वर्तमान चलनिधि प्रबंधन ढांचे को सरल बनाने के लिए; और (ii) चलनिधि प्रबंधन के उद्देश्यों, मात्रात्मक उपायों और टूलकिट को स्पष्ट रूप से संप्रेषित करना शामिल है, के लिए एक आंतरिक कार्यसमूह का गठन करने का निर्णय लिया गया है। जुलाई 2019 के मध्य तक समूह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है।

5. खुदरा प्रतिभागियों के लिए विदेशी मुद्रा व्यापार मंच

विदेशी मुद्रा के उपयोगकर्ताओं (जैसे लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई) निर्यातकों और आयातकों, व्यक्तियों, आदि) के लिए उचित और पारदर्शी मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए बाजार बुनियादी ढांचा तैयार करने की दृष्टि से, रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2017 में एक चर्चा पत्र जारी किया था जिसमें खुदरा विक्रेताओं के लिए एक विदेशी मुद्रा व्यापार मंच स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था जो ग्राहकों को एक इंटरनेट-आधारित एप्लिकेशन के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंच प्रदान करेगा, जिस पर वे बाजार की समाशोधन कीमतों पर विदेशी मुद्रा खरीद / बेच सकते हैं। मौजूदा खंडित बाजार माइक्रोस्ट्रक्चर को एकीकृत करके, यह प्लेटफॉर्म मूल्य निर्धारण को पारदर्शिता प्रदान करेगा और आर्डर के आकार को देखे बिना, सभी ग्राहकों के लिए बेहतर मूल्य निर्धारण के लिए अग्रणी बाजार निर्माताओं के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अब भारतीय समाशोधन निगम (सीसीआईएल) द्वारा विकसित किया गया है और उपयोगकर्ताओं

द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। उपयोगकर्ताओं के लिए अगस्त 2019 की शुरुआत से लेन-देन के लिए मंच उपलब्ध होगा।

मंच के लिए परिचालन दिशानिर्देश पर परिपत्र जून 2019 के अंत तक जारी किया जाएगा।

6. मनी मार्केट दिशानिर्देशों की व्यापक समीक्षा

एक अच्छी तरह से काम करने वाला मुद्रा बाजार, अन्य वित्तीय बाजारों में मूल्य निर्धारण और चलनिधि के लिए बुनियादी आवश्यकता होने के अलावा मौद्रिक नीति संचरण की शृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। रिजर्व बैंक ने विभिन्न मनी मार्केट उत्पादों-कॉल मनी, रेपो, वाणिज्यिक पेपर, जमा प्रमाणपत्र और अन्य ऋण साधनों के साथ एक वर्ष से कम समय के लिए मूल परिपक्वता के साथ, आदि को कवर करने के लिए समय समय पर नियम जारी किए हैं जिसका उद्देश्य जारीकर्ता, निवेशक और अन्य प्रतिभागी के संदर्भ में उत्पादों में स्थिरता लाने का है, विभिन्न मनी मार्केट उत्पादों को कवर करने वाले मौजूदा नियमों को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव है। इन दिशानिर्देशों से मुद्रा बाजारों की पारदर्शिता और सुरक्षा में सुधार होगा।

जुलाई 2019 के अंत तक जनता की प्रतिक्रिया के लिए मनी मार्केट पर एक मसौदा निर्देश जारी किया जाएगा।

7. सरकारी प्रतिभूति बाजार में खुदरा भागीदारी

यह आरबीआई का प्रयास रहा है कि सरकारी प्रतिभूति बाजार में खुदरा भागीदारी बढ़े। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और प्राथमिक डीलरों के अलावा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा अनुमोदित निर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंजों को पहले ही अपने स्टॉक ब्रोकर्स / खुदरा प्रतिभागियों की बोलियों को (उनके ग्राहक को प्रदान किए गए एक वेब आधारित एप्लिकेशन) के माध्यम से एकत्र करने के लिए एग्रीगेटर्स / फेसिलिटेटर के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई है और भारत सरकार के प्रतिभूतियों की प्राथमिक नीलामी के गैर-प्रतिस्पर्धी खंड के तहत एक समेकित बोली प्रस्तुत करनी होगी। यह भी निर्णय लिया गया है कि निर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंजों को अपने स्टॉकब्रोकर/अन्य खुदरा प्रतिभागियों की बोलियों को एकत्र करने और राज्य विकास ऋण (एसडीएल) की प्राथमिक नीलामी के गैर-प्रतिस्पर्धी खंड के तहत एक समेकित बोली प्रस्तुत करने

के लिए एग्रीगेटर्स / फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाए। इन उपाय को संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से लागू किया जाएगा।

III. भुगतान और निपटान प्रणाली

8. रिज़र्व बैंक द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों के लिए प्रभार की समीक्षा

रिज़र्व बैंक अपने तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) के माध्यम से बड़े मूल्य के तात्कालिक निधि अंतरण और अन्य निधि अंतरण के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एमईएफटी) सिस्टम के माध्यम से किए गए लेन-देन के लिए बैंकों से न्यूनतम शुल्क वसूलता है। फलस्वरूप, बैंक अपने ग्राहकों पर शुल्क लगाते हैं। डिजिटल फंड गतिविधि को गति प्रदान करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि आरटीजीएस और एनईएफटी प्रणालियों में संसाधित लेनदेन के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए शुल्कों को हटा दिया जाए। बैंकों से, बदले

में, अपेक्षित होगा कि वे इस लाभ को अपने ग्राहकों तक पहुंचाएं। इस संबंध में बैंकों को एक सप्ताह के भीतर निर्देश जारी कर दिए जाएंगे।

9. एटीएम इंटरचेंज शुल्क संरचना की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन

जनता द्वारा स्वचालित टेलर मशीनों (एटीएम) का उपयोग काफी बढ़ रहा है। हालांकि, एटीएम प्रभार और शुल्क को बदलने की लगातार मांग होती रहती है। इसका समाधान करने के लिए, यह निर्णय लिया गया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) की अध्यक्षता में, सभी हितधारकों को शामिल करते हुए एक समिति का गठन किया जाए जो एटीएम प्रभार और शुल्क के पूरे विस्तार की जांच करें। अपनी पहली बैठक होने के दो महीने के भीतर समिति अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। समिति की संरचना और कार्यक्षेत्र एक सप्ताह के भीतर जारी किया जाएगा।